जनसत्ता

संकट और सवाल

महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक घोटाले का मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं पड़ा था कि अब बंगलुरू के श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक के ग्राहकों की नींद उड़ गई है। रिजर्व बैंक ने दस जनवरी से इस बैंक से पैंतीस हजार रुपए से ज्यादा राशि की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। ग्राहक अब छह महीने में पैंतीस हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। जाहिर है, करीब बैंक के नौ हजार ग्राहकों के समक्ष गंभीर संकट खड़ा हो गया है और यह वैसा ही मामला है, जैसा कि पीएमसी बैंक घोटाला उजागर होने के बाद देखने को मिला था। बंगलुरू का ये सहकारी बैंक भी बासठ बड़े कर्जदारों से पैसा वसूल पाने में नाकाम रहा और इस वजह से उसकी साढ़े तीन अरब से ज्यादा की रकम एनपीए में तब्दील हो गई। बैंक अब नए कर्ज भी नहीं दे पाएगा, न कोई निवेश कर सकेगा, न ही संपत्ति बेच सकेगा। हालांकि बैंक अपने स्तर पर सफाई दे रहा है कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और सभी को उनकी जमा राशि लौटा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ग्राहक बैंकों के इस कुप्रबंधन का खमियाजा कब तक उठाते रहेंगे? क्यों नहीं बैंक ने पहले से ऐसे कदम उठाए जिससे ये नौबत ही नहीं आती?

बैंक से पैसा निकालने पर जब अचानक से पाबंदी लगा दी जाती है तो ग्राहक मुश्किल में फंस में जाते हैं। सहकारी बैंकों में खाता खुलवाना लोग इसलिए भी ज्यादा पसंद करते हैं कि ये बैंक दूसरे व्यावसायिक बैंकों के मुकाबले ब्याज ज्यादा देते हैं। इसलिए छोटे-मोटे कारोबारियों से लेकर सेवानिवृत्त लोग तक जीवनभर की कमाई बैंकों में एफडी के रूप में रखते हैं और एफडी का ब्याज ही इनकी आमद का बड़ा जरिया होता है। ऐसे में अगर पैसा मिलना बंद हो जाए तो कैसे-कैसे गंभीर संकटों से दो-चार होना पड़ता है, ये पीएमसी के ग्राहकों की पीड़ा से हम देख चुके हैं। अपने पैसे के लिए लोग बैंकों के दरवाजे पर सिर पटक-पटक मर गए थे, लेकिन पैसा नहीं निकल पाया था। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग पैसे को तरस गए थे। घर के राशन से लेकर बच्चों की फीस तक भरना मुश्किल हो गया था। पीएमसी बैंक के कुछ ग्राहकों की तो पैसा डूब जाने के सदमे में जान तक चली गई। अगर लोगों की जमा गाढ़ी कमाई इस तरह से बैंकों में फंसने लगेगी तो लोग क्या करेंगे, यह सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब न बैंकों के पास है, न सरकार और रिजर्व बैंक के पास।

सहकारी बैंक हों या बड़े सरकारी और निजी बैंक, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बैंकों में घोटालों और गड़बड़ियों का खुलासा होता रहा है, उससे लोगों का बैंकों पर से भरोसा उठ गया है। आज हर बैंक ग्राहक इस खौफ में जी रहा है कि कहीं उसके साथ ऐसा न हो जाए। जब किसी बैंक पर ग्राहकों के धन की निकासी जैसी कठोर पाबंदियां लगा दी जाती हैं तो पैसा लंबे समय तक के लिए अनिश्चितता में फंस जाता है। उस वक्त कोई यह नहीं बता सकता कि अंतिम समाधान कितने महीनों या सालों में होगा और लोगों की फंसी पूंजी कब निकलेगी। रिजर्व बैंक को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर किसी बैंक पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है तो पहले यह सुनिश्चित हो कि लोगों के पैसे जब्त न हों।

कुदरत का कहर

पहाड़ों का जीवन यों तो हर समय कठिन होता है, पर सर्दी में कुछ अधिक समस्याओं से घिर जाता है। जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, तो कई खतरे बढ़ जाते हैं, जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है। मैदानी हिस्सों में रहने वालों के लिए बर्फबारी के नजारे कुतूहल और रोमांच से भरे होते हैं, पर जिन्हें उसी बर्फ में अपनी रोजमर्रा की चीजें जुटानी और अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, उनके सामने जोखिम भी कम नहीं होते। कभी बर्फीली आंधी उन्हें अपने आंचल में लपेट लेती है, तो कभी ऊंची चोटियों से टूट कर गिरे हिमखंड उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। हर साल सर्दी में बर्फीली आंधी और हिमस्खलन की वजह से अनेक लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इस बार भी अब तक कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों से छह सैनिकों समेत बारह लोगों के हिमस्खलन में दब कर मारे जाने की खबर है। एक सैन्य शिविर पर बर्फ का पहाड़ आ टूटा और कई जवान मारे गए। सैनिकों पर ऐसे खतरे हर समय मंडराते रहते हैं। वे सिर्फ दुश्मन की गलत नीयत का शिकार नहीं होते, कुदरत भी उन्हें कम चुनौती नहीं देती। इसी तरह कई सैलानी लापरवाही से, तो स्थानीय लोग किसी चूक की वजह से बर्फ में दफन हो जाते हैं।

आमतौर पर हिमस्खलन वहां ज्यादा खतरनाक होता है, जहां ऊंची पर्वत चोटी और नीचे गहरी खाई होती है। उधर से कोई सड़क गुजर रही हो या फिर कोई सुरक्षा चौकी बनाई गई हो, तो उधर से गुजरने वालों पर हिमस्खलन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। बरसात में पहाड़ों के टूट कर गिरने से भी ऐसे हादसों की आशंका बनी रहती है। यों सरकार की तरफ से हर तरह के जोखिम से पार पाने के एहतियाती उपाय किए जाते हैं, फिर भी कहीं चूक रह जाने से बड़े हादसे हो ही जाते हैं। अक्सर इस मौसम में मैदानी भागों से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी देखने पहाड़ों का रुख करते हैं। रोमांच के लिए वे अक्सर जोखिम उठाते देखे जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों की मनाही के बावजूद या फिर उन्हें चकमा देकर खतरनाक ढलानों वाली जगहों पर तस्वीरें खिंचाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी समय मौसम अचानक बदलने या पहाड़ की चोटी से बर्फ खिसकने से वे उसकी चपेट में आ जाते हैं। कश्मीर में हुए हादसों में कई सैलानी इसी मनमानी और असावधानी के चलते मारे गए।

जब भी कोई हादसा होता है तो स्वाभाविक ही सुरक्षा इंतजामों की तरफ अंगुली उठने लगती है। मगर जिन मामलों में खुद सतर्कता बरत कर सुरक्षित रहा जा सकता है, उसमें असावधानी विवेक की निशानी नहीं कही जा सकती। हां, कश्मीर के पहाड़ों पर दुश्मन देश की हरकतों पर नजर रखने, आतंकी घुसपैठियों को रोकने के लिए सुरक्षा चौकियां बनाना जरूरी है। मगर हर साल कई सैनिक सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं कि वे खतरनाक रास्तों पर गश्ते देत या फिर जोखिम वाली जगहों पर बने शिविरों में तैनात रहते हैं और हिमस्खलन या पहाड़ खिसकने से उनके नीचे दब जाते हैं। सैनिकों को इस जोखिम से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आखिर सरकार की ही है। आज जब सुरक्षा संबंधी तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है, मौसम और कुदरत की हलचलों पर नजर रखने के अत्याधुनिक उपकरण बन चुके हैं, फिर भी हमारे सैनिकों को ऐसे जोखिमों के बीच अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

कल्पमेधा

चुनाव में पार्टी उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं होती, जितना उम्मीदवार और उम्मीदवार की विचारधारा उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना उसका आचरण।
-महात्मा गांधी

नया गठजोड़ और चुनौतियां

संजीव पांडेय

सऊदी अरब को कतर-तुर्की-ईरान के त्रिगुट से परेशानी भी है और नाराजगी भी, क्योंकि इन तीन देशों ने मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देशों को भी सऊदी अरब के गुट के खिलाफ लामबंद कर दिया है। हालांकि इंडोनेशिया को सऊदी अरब ने अपने व्यापारिक रिश्तों और निवेश का हवाला देकर कुछ हद तक मना लिया है, लेकिन मलेशिया पूरी तरह से इस्लामिक देशों के नए समूह को लेकर सक्रिय है।

पिछले महीने मलेशिया में इस्लामिक देशों के सम्मेलन से सऊदी अरब के साथ-साथ चीन और अमेरिका सहित कई बड़ी ताकतों की नींद उड़ गई है। मलेशिया में हुए इस सम्मेलन में सऊदी अरब के तीन घोर विरोधी देशों- कतर, ईरान और तुर्की की सक्रियता ने उसके समक्ष एक चुनौती पेश कर दी है। हालांकि इस बैठक में इस्लामिक दुनिया से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों से दूरी बनाई गई, लेकिन सऊदी अरब को साफ संकेत भेजा गया कि उसके नेतृत्व वाले इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआइसी) के कामकाज से कई देश खुश नहीं हैं। इस सम्मेलन का असर अब दिखने लगा है। इसके बाद ही ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी अमेरिकी हमले में मारे गए। उधर, पाकिस्तान इस बैठक के बाद नए 'इस्लामिक ब्लॉक' का भय दिखा कर सबसे ज्यादा लाभ उठाने के लिए सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान अपनी कुछ शर्तों पर सऊदी अरब से बातचीत कर रहा है। भारत की चिंता यह है कि नए इस्लामिक गुट के दबाव में सऊदी अरब के साथ बढ़ रही दोस्ती प्रभावित हो सकती है।

फिलहाल इस्लामिक देशों की आपसी राजनीति पर इस सम्मेलन का असर पड़ना लाजिमी है। इस्लामिक देशों के नए गुट के गठन से सऊदी अरब डरा हुआ है। यह समूह भविष्य में ओआइसी के लिए चुनौती बन कर खड़ा होगा। ओआइसी का गठन 1959 में हुआ था। इस संगठन पर सऊदी अरब सबसे ज्यादा हावी है। लेकिन अब कई इस्लामिक देश दबी जुबान में सऊदी अरब के दबदबे के खिलाफ बोलने लगे हैं। ऐसे कई देशों का कहना है कि सऊदी अरब और उसके कुछ खास सहयोगी देश व्यापारिक हितों के लोभ में दुनिया भर के मुसलमानों की समस्या को ओआइसी के मंच से नहीं उठने नहीं देते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब समेत कई इस्लामिक देशों के व्यापारिक हित चीन और भारत के तेल बाजार से जुड़े हैं। चीन और भारत सऊदी अरब के लिए बड़े तेल बाजार हैं। चीन अकेले प्रतिदिन पंद्रह लाख बैरल तेल सऊदी अरब से आयात करता है। भारत प्रतिदिन चालीस लाख बैरल तेल का आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आता है। ऐसे में दुनिया के दो बड़े तेल बाजार सऊदी अरब किसी कीमत पर नहीं खोना चाहेगा।

दरअसल, इस समय पश्चिम से लेकर मध्य एशिया तक तुर्की और ईरान के अपने हित हैं। ईरान का विरोध सुन्नी सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक है। वहीं, तुर्की सऊदी अरब के राजपरिवार को हमेशा चुनौती देता रहा है। तुर्की अफ्रीका से लेकर एशियाई इस्लामिक देशों की गुपचुप मदद करता आया है। दूसरी ओर, तुर्की कुछ इस्लामिक देशों के राजपरिवारों से हमेशा नाराज चलता आया है। कतर को भी राजपरिवारों द्वारा शासित कुछ इस्लामिक देश शक की नजर से देखते हैं। उन्हें शक यह है कि कतर भी मुसलिम ब्रदरहुड को मदद देता है। कतर से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राजपरिवारों की नाराजगी इसी कारण है। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की तुर्की में हत्या के बाद सऊदी अरब और तुर्की के संबंध खासे खराब हो गए हैं। तुर्की के इसके लिए सीधे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आरोपी मानता है।

सऊदी अरब को कतर-तुर्की-ईरान के त्रिगुट से परेशानी भी है और नाराजगी भी, क्योंकि इन तीन देशों ने मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देशों को भी सऊदी अरब के गुट के खिलाफ लामबंद कर दिया है। हालांकि इंडोनेशिया को सऊदी अरब ने अपने व्यापारिक रिश्तों और निवेश का हवाला देकर कुछ हद तक मना लिया है, लेकिन मलेशिया पूरी तरह से इस्लामिक देशों के नए समूह को लेकर सक्रिय है। यही कारण है कि मलेशिया में आयोजित बैठक के बाद सऊदी अरब को यह अंदाज हो गया है कि उसके नेतृत्व को अरब जगत में भविष्य में और भारी चुनौती मिलेगी।

सऊदी अरब ने मलेशिया में आयोजित इस्लामिक देशों की बैठक को विफल करने की पूरी कोशिश की थी। उसे इसमें आंशिक सफलता तब मिली, जब उसने पाकिस्तान को बैठक में शामिल नहीं होने के लिए राजी कर लिया। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की भू-राजनीति में पाकिस्तान की दखलदांजी लंबे समय से रही है। इसका मुख्य कारण पाकिस्तान की सैन्य ताकत है। मलेशिया की बैठक में शामिल नहीं होने के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के आग्रह को मान गया।

हालांकि विशेषज्ञों को आश्चर्य इस बात पर है कि कश्मीर के मुद्दे पर पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के साथ खुल कर मलेशिया और तुर्की आए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान लगातार दबी जुबान से कहता रहा है कि सऊदी अरब वैश्विक मुसलिम हितों की बलि चढ़ा रहा है, क्योंकि उसके व्यापारिक हित भारत जैसे मुल्कों के साथ जुड़े है। बताया जाता है कि मलेशिया में आयोजित होने वाले बैठक के पीछे पाकिस्तान का भी दिमाग था। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान मलेशिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस्लामिक देशों की बैठक आयोजित करने के लिए सहमति बनी थी। लेकिन बैठक के आयोजन के ठीक पहले पाकिस्तान सऊदी अरब के दबाव में बैठक में शामिल होने से पीछे हट गया। पाकिस्तान बैठक से क्यों पीछे हटा, इसका खुलासा तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने किया। एर्दोगन के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक सहयोग बंद करने और उसके यहां रह रहे चालीस लाख पाकिस्तानी कामगारों को वापस भेजने की धमकी दी थी। सऊदी अरब में कार्यरत पाकिस्तानी कामगारों से पाकिस्तान को अरबों डॉलर सालाना की आय होती है। यही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यह भी धमकी दी थी कि वह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद अपने अरबों डॉलर निकाल लेगा।

लेकिन मलेशिया बैठक के मामले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक सौदा किया। पाकिस्तान की नाराजगी यह थी कि सऊदी अरब भारत के साथ अपने व्यापारिक हितों की आड़ में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की इस नाराजगी को दूर किया है। पाकिस्तान गए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल ने पाकिस्तान से वादा किया है कि जल्द ही कश्मीर को लेकर ओआइसी के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी। पाकिस्तान इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। हालांकि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर तो हमेशा उग्र रहा है, लेकिन चीन में उइगुर मुसलमानों के उत्पीड़न पर चुप्पी साधे रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान में बन रहे चीन-पाक आर्थिक गलियारे में चीन ने साठ अरब डॉलर का निवेश किया है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के स्वार्थ की क्यों बात करें? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश चीन के तेल बाजार को खोना नहीं चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश इस समय चीन है।

मलेशिया की बैठक और ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत को जोड़ कर भी देखा जा रहा है। दरअसल, मलेशिया में इस्लामिक देशों की बैठक से इजराइल जैसे देश भी परेशान हैं। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते बेहतर हुए हैं। इस कारण इजराइल कतई नहीं चाहेगा कि इस्लामिक देशों का कोई नया गुट खड़ा हो और उसकी परेशानी बढ़ा दे। सऊदी अरब के खिलाफ इजराइल अब उग्र नहीं है। सऊदी अरब पर कई इस्लामिक देश लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फिलस्तीन के मसले पर सऊदी अरब और इजराइल के बीच अंदरखाने समझौता हो गया है। यह भी एक सच्चाई है कि कासिम सुलेमानी और हमास के संबंध काफी मधुर रहे हैं और सुलेमानी ने हमास की खूब मदद की है।

गायब होते गांव

रीतेंद्र कंवर शेखावत

एक प्यारा शेर है कि 'मर ही जाता मैं शहर में बच गया, गांव की शीतल हवाएं साथ हैं।' आज भी गांवों में जाएं तो वहां शीतल हवाएं, सघन अमराई और तालाब मिलेंगे। यह और बात है कि ऐसे मनोरम दृश्य वाले अनेक गांवों को महानगर निगलता चला जा रहा है। मिट्टी की एक खुशबू होती है, इसका पता तब चलता है, जब सब कुछ छोड़ कर गांव से शहर में बसते हैं। शहर, जहां चारों ओर कंक्रीट दिखता है। मिट्टी के लिए थोड़ी बहुत जगह या तो बाग-बगीचों और पार्कों में होती है या फिर घर के गमलों में। एक तरह से देखा जाए तो शहर कृत्रिम हैं, जबकि गांव सहजता से बसते हैं। जाहिर है, शहर में आने के साथ ही मिट्टी की अपनी खुशबू से भी दूर हुआ। जब अपने गांव से दूर हो गया, तब उसकी मिट्टी की खुशबू और उसकी कीमत का अंदाजा हुआ।

गांव में रहने की अपनी समस्याएं भी हैं, इसके बावजूद गांव मुझे आकर्षित करता है। लोगों में आपसी तालमेल होता है और एक-दूसरे का हर काम में सहयोग करते हैं, चाहे वह खेती में हो या कोई सामाजिक दायित्व का कार्य जैसे शादी-ब्याह हो। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के भीतर बहुत सरलता, निश्छलता और अपनापन है। ये बातें शहरी लोगों के मुकाबले ज्यादा मानवीय होने का परिचय देती हैं।

सही है कि गांवों में शहरों जैसी तकनीक नहीं आई है, लेकिन आवश्यकता भर सुविधाएं अब यहां भी पहुंच गई हैं। लोग गांव में भी अब आमतौर पर गैस-चूल्हे का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे घरों में पंखा भी दिख जाता है और बिजली रहने पर टेलीविजन का प्रयोग भी। कुछ जगहों को छोड़ कर अधिकतर जगह सड़कें भी बन चुकी हैं और आवाजाही के साधन भी मिलने लगे हैं। हालांकि अब दूसरी तरह से हालात इतने खराब हैं कि गांव के लोग खुद भी वहां रहना नहीं चाहते। मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से गांवों में आजीविका और पेट पालने के साधन बहुत कम हो गए हैं। एक त्रासदी यह कि गांव भी राजनीति की चपेट में आ चुके है, जिससे दंगे-फसाद की समस्याएं आम होती जा रही हैं। लोगों की थाना-अदालतों में आवाजाही बढ़ी है। दरअसल, गांव अब सिर्फ खेतों के बीच कुछ कच्चे और ज्यादा पक्के घरों की आबादी भर रह गए हैं, जहां जीवन-रस पूरी तरह सूख-निचुड़ चुका है। पढ़ी-लिखी नई पौध गांव में रहना नहीं चाहती। चमक-दमक और शहर की चकाचौंध ही आधुनिकता और प्रगति का पर्याय बन चुकी है।

दुनिया मेरे आगे

ऐसे में गांव की तस्वीर एकदम बदरंग और दयनीय दिखाई पड़ रही है। गांव के धूल-धूसरित जीवन से सब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मैं गांव और उसकी शीतल छांव चाहता हूं। नदी, तालाब, हरियाली चाहता हूं। शहरों में यह सब दुर्लभ है। लेकिन मेरे या आपके चाहने से क्या होगा! स्मृतियों में रहा-बचा गांव यथार्थ में अब नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा और गरीबी आज भी भयानक स्तर तक कायम हैं। सरकारी स्कूलों के हालात बेहद चिंताजनक है। इसलिए जब तक वहां के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने लगती, तब तक वहां के जीवन में कोई बदलाव आएगा, ऐसा सोचना शायद खामखयाली है। अशिक्षा के कारण ही गांवों में आज भी अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां जमी हुई हैं। लोग हर समस्या को लेकर बाबाओं और तांत्रिकों की मदद लेते हैं। महिलाओं के पास न सपने हैं, न उन सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान। जातिगत ऊंच-नीच का भेद और शोषण आज भी जड़ें जमाए हुए है।

दूसरी ओर, शहरों के अनाप-शनाप और उसके अनियोजित विकास के दैत्य ने विगत डेढ़-दो दशकों में ही कितने ही गांवों को निगल लिया। विकास के नाम पर हर तरफ लोगों को उजाड़ा जा रहा है और लोग खुश हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ रही हैं। जो युवा पहले साइकिल चला कर बीस किलोमीटर तक आना-जाना मजे से कर लेता था, अब उसे साइकिल अछूत-सी लगती है। उसे महंगी बाइक चाहिए। शहरी चमक-दमक को ही अब जीवन-स्तर का पर्याय समझा जा रहा है।

आज एक गांव की कई फसली उपजाऊ धरती बिक कर जब शहर की सीमा में समा कर पलक झपकते अपनी छाती पर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर लेती है, तो यह सिर्फ एक गांव और उसकी देहाती बस्ती का नष्ट हो जाना नहीं है, बल्कि उस गांव का रहन-सहन, रीति-रिवाज, वहां का लोक जीवन, कथा-किस्से, खलिहान, खाड़े, खानपान, पालतू पशुओं के रंभाने की आवाजें, उनके बाड़े, खुरों के निशान, गोधूलि सब कुछ नष्ट हो जाना है, जिसकी भरपाई किसी तरह संभव नहीं।

मैंने गौर किया है कि इंसान कितना भी स्वार्थी क्यों नहीं हो, लेकिन अंतिम समय में जैसे उसे अहसास हो जाता है कि जीवन का असली मतलब अपनों के संग मिल कर जीना है। होना यह चाहिए कि गांव की मिट्टी में पले लोग शहर से अच्छी चीजें सीख कर गांव में लौटें, प्रयोग करें और गांव को भी उन्नत बनाने में सहयोग करें।

चिंता की बात

देश के आर्थिक हालात दिनों-दिन चिंताजनक होते जा रहे हैं। जीडीपी पांच फीसद तक लुढ़क गई, बेरोजगारी दर पैंतालीस साल के उच्चतम स्तर पर है, खुदरा महंगाई दर साढ़े पांच साल के उच्चतम स्तर पार कर 7.35 फीसद पर पहुंच गई है, क्रय शक्ति दशक के निम्नतम स्तर पर है, रिजर्व बैंक से ली गई राशि से अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा, नए स्टार्टअप खुलने से ज्यादा पहले से खुले स्टार्टअप बंद होते जा रहे हैं और अब आने वाले वित्त वर्ष में नौकरियों में और छंटनी के साफ संकेत आ रहे हैं। ये स्थिति कतई अच्छी नहीं है, न ही इस स्थिति को व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी के जरिए प्रसारित इन थोथी दलीलों- मसलन, रोजगार इसलिए नहीं है कि लोग सरकारी नौकरी ही चाहते हैं और क्रय शक्ति नहीं है तो लोग तानाजी-छपाक कैसे देख रहे हैं और कांग्रेस के समय में तो जैसे रामराज चल रहा था, वगैरह-वगैरह, से लंबे समय तक ढक सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में जब जब देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही थी, तब राजनीतिक पार्टियों की अर्थव्यवस्था सुधर रही थी। भाजपा की कुल आय 2017-18 में 1027 करोड़ थी, जो एक साल में बढ़ कर 2018-19 में 2410 करोड़ हो गई। दूसरी ओर कांग्रेस की आय 2017-18 में 199 करोड़ थी, जो 2018-19 में बढ़ कर 918 करोड़ रुपए हो गई। यहां यह जानना भी जरूरी है कि ये आंकड़े इन पार्टियों के दिए हुए हैं, सार्वजनिक हैं।

देश न तो छपाक से चलेगा और न जामिया-जेएनयू पर राजनीति से बढ़ेगा। देश का विकास तभी होगा, जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा। जिन युवाओं के दम पर दुनिया के सबसे युवा देश यानी भारत अपने विकास की उम्मीद लगाए बैठा है, उन युवाओं को शिक्षा और रोजगार कैसे मिले, विमर्श इस पर केंद्रित होना चाहिए। जब जनता इसका दबाव बनाएगी तो सत्ता और विपक्ष को इस पर काम करने को मजबूर होना पड़ेगा, वरना ये राजनीतिक ताकतें सबको फिजूल के मुद्दों में उलझाए रख कर अपनी अर्थव्यवस्था संवारती रहेंगी और देश आर्थिक बदहाली के कीचड़ में छपाक-छपाक करता रहेगा।

● *मो. ताबिश, जामिया विवि, नई दिल्ली*

किसानी का संकट

भारतीय अर्थव्यवस्था इन दिनों मंदी और आसमान छूती महंगाई की समस्या से जूझ रही है। हमें यह देखना होगा कि इस मंदी के बीच में खाद्य पदार्थों की कीमतें क्यों आसमान छू रही हैं? क्या ये अचानक खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि का संकेत है? निश्चित रूप से नहीं। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने का प्रमुख कारण आपूर्ति में कमी है, जिसका प्रमुख कारण बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके साथ ही जो चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वह है किसानों का खेती से मोहभंग होना। एनएसएसओ के रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2011 के बीच लगभग नब्बे लाख किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात पर विचार करना अति आवश्यक है कि जब हमारी सरकारें किसानों के लिए तरह-तरह की कल्याण योजनाएं ला रही है, तो फिर उन्हें खेती छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? इस बात की तहकीकात करना जरूरी है कि किसानों के लिए बनी योजनाएं धरातल पर किस हद तक कामयाब हुई हैं? सरकार को खाद्य पदार्थों की महंगाई से निपटने के लिए दीर्घकालिक और सतत योजनाओं पर काम करना पड़ेगा जैसे -कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के उपाय करने, शीत भंडार गृहों के निर्माण, ताकि कम उपज के समय इसमें रखे गए अनाज काम आ सकें।

● *अभिषेक पाल, प्रयागराज*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कैसे होगा पुलिस सुधार

संयुक्त राष्ट्र के मानदंड को अगर माने तो हमें एक लाख की आबादी पर दो सौ बाईस पुलिसकर्मी चाहिए। मगर हम इस वक्त केवल एक सौ सैंतीस पुलिसकर्मियों से काम चला रहे हैं। मतलब आज भी देश में साढ़े पांच लाख पुलिसकर्मियों की कमी है। अकेले उत्तर प्रदेश में एक लाख उनतीस हजार पद खाली पड़े हैं। ऐसे में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत से क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि पुलिस सुधार के लिए यह भी एक कदम जरूर है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इस पर जो आदेश दिया था, वह गृह मंत्रालय में धूल फांक रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ हफ्ते पहले पच्चीस हजार होम गार्ड जवानों को घर बैठा दिया गया था। केवल पद का नाम बदल देने से कुछ नहीं होगा। बिना छुट्टी के अठारह घंटे काम कराए जाते रहेंगे। ऐसे में हम पेशेवर पुलिसिंग खोजेंगे तो कहां से मिलेगा?

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

कंपनियों की मनमानी

वर्तमान में देश की दूरसंचार सेवाओं में बड़ी मूल्य वृद्धि ने आम उपभोक्ता में हाहाकार मचा रखा है। दूरसंचार कंपनियों के मनमाने आचरण ने मध्यम वर्ग को दूरसंचार सेवाओं से दूर रहने को मजबूर कर दिया है। सेवाओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अस्तित्व को औचित्यहीन कर दिया है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ बेची जाने वाले सिमकार्ड को इनकमिंग के लिए रिचार्ज कराना और कॉल की दरों में भीषण वृद्धि करना, जबरदस्ती आवश्यकता से अधिक प्रतिदिन डाटा देकर पैसे वसूलना, जिसे केवल कॉल की आवश्यकता है उसे भी जबरदस्ती डाटा बेचा जाना.. आदि भांति-भांति की योजनाएं मध्यम वर्ग और गरीबों की जेब पर एक तरह से हमला है। आम उपभोक्ताओं को ट्राई से ही आखिरी उम्मीद बची है, किंतु ट्राई द्वारा भी कंपनियों को मनमानी करने से न रोकना उनमें व्यवस्था के विरुद्ध क्षोभ भर रहा है। आज दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां उपभोक्ताओं से 4जी का पैसा लेकर 2जी जैसी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। साथ ही, कंपनियों द्वारा महीने को अट्ठाईस दिन का बना दिया जाना उपभोक्ताओं के साथ बड़ा धोखा है। सरकार द्वारा इन सेवाओं पर अधिकतम टैक्स लिया जा रहा है, जिसका भार भी अंततः आम उपभोक्ताओं पर ही पड़ रहा है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार और ट्राई को दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए।

● *महेंद्र नाथ चौरसिया, सिद्धार्थनगर*

नई दिल्ली

www.readwhere.com